viuh ckr

तिब्बत की उपेक्षा भारत के लिए घातक

चीन सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के परिणामस्वरूप तिब्बत में जारी आत्मदाह की घटनायें विचलित करने वाली हैं। हाल ही दो बच्चों के बाप ने अपने शरीर में अपने ही हाथों आग लगाकर आत्मबलिदान किया है। किसी भी देष की आजादी की लड़ाई में आत्मबलिदान की परंपरा रही है। भारत भी इसका उदाहरण है। फिर भी तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की घटनायें दिल दुखाने वाली हैं। चीन सरकार ऐसी घटनाओं को ''आत्महत्या'' का नाम दे रही है, जो कि सरासर गलत है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे तिब्बतियों के आत्मदाह को आत्मबलिदान कहना उचित होगा, न कि आत्महत्या। चीन सरकार तिब्बतियों के आत्मदाह को आत्महत्या के रूप में प्रचारित करके तिब्बती आंदोलन के संबंध में पूरे विश्व को गुमराह कर रही है।

तिब्बत में दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह का कारण है चीन सरकार का अमानवीय व्यवहार। अभी सितंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार परिषद् की जेनेवा बैठक में इस मसले पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। तमाम प्रमाणों के आधार पर पाया गया कि चीन सरकार तिब्बत में व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। वह वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा मानवीय मूल्यों की घृणित तरीके से उपेक्षा कर रही है। तिब्बत में साजिषपूर्वक चीनी मूल के लोगों की संख्या बढ़ाकर तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तिब्बत के अंदर उद्योग–व्यापार समेत सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी लोगों का वर्चस्व कायम कर दिया गया है। चीनी लोगों के लिए तिब्बत में सुख–सुविधा–सम्मान के नए–नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप तिब्बती अपने ही देष में गुलाम से भी बदतर जीवन जीने को बाध्य हो गये हैं।

चीन सरकार षड्यंत्रपूर्वक तिब्बत में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रों को बर्बाद कर रही है। मठ–मंदिर चीनी सेना तथा प्रषासन के अन्यायपूर्ण घेरे में हैं। तिब्बत की बौद्ध संस्कृति के प्रति पूरे संसार में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। लेकिन साम्राज्यवादी चीन सरकार शांति, अंहिसा एवं करूणापूर्ण बौद्ध संस्कृति को मटियामेट कर रही है। भोगवादी चीन सरकार अंदर–ही–अंदर इस तथ्य को भलीभाँति समझ रही है कि उसने तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कायम किया है। एक दिन तिब्बत से उसे जरूर खदेड़ा जाएगा। इसीलिए वह तिब्बत को योजनापूर्वक खोखला कर रही है।

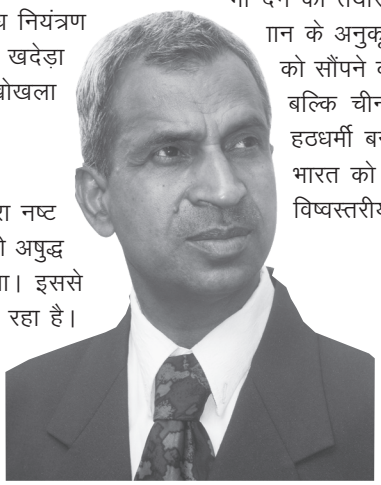

तिब्बत में प्राकृतिक संसाधन चीन सरकार द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण खतरे में है। माटी अषुद्ध । पानी अषुद्ध। हवा अषुद्ध। सब अषुद्ध हो गया। इससे संपूर्ण एषिया, विषेषकर भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप आदि इसी के नतीजे हैं। यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। चीन की प्रत्येक नीति तिब्बत को बर्बाद कर रही है। तिब्बती इसी खराब परिस्थिति की ओर विष्वजनमत का ध्यान खींचने के लिए आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि तिब्बत आजाद हो तथा परमपावन दलाईलामा जी की तिब्बत में गरिमापूर्ण वापसी हो।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत मामले पर गंभीर चर्चा वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। इससे तिब्बती संघर्ष में नई जान आ गई है। सभी तिब्बत समर्थक अपने आंदोलन को निर्णायक ऊँचाई तक पहुँचाने में जुट गए हैं। ऐसे अवसर पर भारत की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वे अक्टूबर में होने वाली अपनी चीन यात्रा के दौरान तिब्बत के मामले को जरूर उठायेंगे। ज्ञातव्य है कि चीन सरकार तिब्बत होकर भारत में चीन में निर्मित घटिया किस्म की वस्तुओं की बहुत ही कम कीमत में बिक्री कर रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तथा भारतीय कारीगरों एवं उत्पादकों को काफी नुकसान हो रहा है।

चीन की सरकार तिब्बत में भारत के खिलाफ मिसाइलें तैनात किए हुए है तथा भारतीय सीमा तक सैनिक सुविधाओं का विस्तार किए हुए है। चीन के सैनिक बार–बार भारतीय भूभाग में घुसपैठ कर रहे हैं। इस प्रकार परतंत्र तिब्बत के कारण भारत की सीमा असुरक्षित है। भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए तिब्बत की आजादी जरूरी है। आजाद तिब्बत पहले की भाँति भारत एवं चीन के बीच एक मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) रहेगा। वैसी दषा में भारत के साथ तिब्बत की सीमा मिलेगी और चीन काफी दूर चला जाएगा। फिर भारत–चीन संबंध भी सुदृढ़ होते जायेंगे। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय हित में अपनी आगामी चीन यात्रा के समय तिब्बत समस्या का निपटारा करना चाहिए।

तिब्बत की आजादी अर्थात् भारत की सुरक्षा। इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दल तिब्बत के मसले को उठायें। भारतीय मीडिया भी उपयुक्त माहौल तैयार करे। चीन को बेनकाब करे। चीन की हठधर्मिता पर रोक लगानी होगी। चीन की सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता भी देने को तैयार नहीं है। तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन के संविधान के अनुकूल विदेषी मामले तथा सुरक्षा विषयों को चीन सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। वह तिब्बत की चीन से आजादी नहीं बल्कि चीन में ही स्वायत्तता मांग रही है। किन्तु चीन सरकार हठधर्मी बनी हुई है। तिब्बत में चीन की हठधर्मिता निंदनीय है। भारत को चाहिये कि वह चीन की दमनात्मक नीति के खिलाफ विष्वस्तरीय संघर्ष को मजबूत करे।

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

तिब्बत मसले के हल की रणनीति पर चर्चा के लिए तिब्बती कार्यबल की 26वीं बैठक

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 07 सितंबर)

चीन–तिब्बत वार्ता पर गठित कार्यदल के सदस्यों की धर्मशाला के कशाग सचिवालय में 5 सितंबर 2013 को शुरू हुई तीन दिवसीय बैठक के अवसर पर एक ग्रुप फोटो। फोटोः डीआईआईआर

चीन के साथ बातचीत करने के लिए बने निर्वासित तिब्बती दल का विस्तार किया गया है और उसकी तीन दिवसीय 26वीं बैठक 5 सितंबर को धर्मशाला में शुरू हुई। हालांकि, इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि इस बैठक के बाद चीन के साथ पहले से चल रही वार्ताओं का नया दौर शुरू हो पाएगा। चीन ने इसके पिछले दौर की वार्ता 2010 में अचानक खत्म कर दी थी और तिब्बती पक्ष को झिड़की भी लगाई थी।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रमुख सिक्योंग लोबसांग सांगे ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें वार्ता के पूर्व विशेष दूत श्री लोदी ग्यारी और पूर्व दूत श्री केलसांग ग्याल्सेन शामिल हुए। इन दोनों राजदूतों ने वर्ष 2002 से 2010 के बीच चले निरर्थक, अक्सर विद्वेषपूर्ण वार्ताओं के नौ दौर के बाद इस्तीफा दे दिया था। चीन–तिब्बत वार्ता के लिए बने कार्यदल के नए सदस्यों में पूर्व कालोन ट्रिपा सामढोंग रिनपोछे, कसुर लोबसांग न्याडाक, सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध मामलों के मंत्री श्री टाशी फुंत्सोक, निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य श्री सोनम फ्रासी, तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट के उप निदेशक श्री फागपा सेरिंग और न्यूयॉर्क स्थित तिब्बत ऑफिस में चीन से संपर्क अधिकारी श्री कुंगा टाशी शामिल हैं। इसके पहले अक्टूबर, 2011, जनवरी 2012 और जनवरी 2013 में इस कार्यदल की तीन बैठकें हो चुकी हैं। कार्यदल की सबसे पहली बैठक 1999 में हुई थी। कार्यदल की भूमिका तिब्बत के मसले के शांतिपूर्ण, बातचीत से परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए नीतियां और रणनीति बनाने के लिए सुझाव देना है।

चीन ने लगातार और अक्सर निंदात्मक तरीके से यह साफ किया है कि वह तिब्बत मसले पर तब ही कोई बातचीत नहीं करेगा, जब इसमें दलाई लामा की व्यक्तिगत हैसियत पर बात हो और यह बातचीत तिब्बती आध्यात्मिक नेता के व्यक्तिगत दूतों से ही हो सकती है। उसने निर्वासित तिब्बती सरकार के मध्यम मार्ग नीति को खारिज कर दिया है जिसमें मांग कमी गई है कि सभी तिब्बती इलाकों को मिलाकर एक प्रशासनिक ईकाई वाला स्वायत्तशासी तिब्बत बनाया जाए और वह कम्युनिस्ट चीन की संप्रभुता के भीतर हो। इस तरह तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ दी गई है। चीन ने तिब्बती पक्ष के इस सहमति को भी खारिज कर दिया है कि तिब्बत की स्वायत्तता की उसकी मांग चीन जनवादी गणराज्य के संवैधानिक प्रावधानों के भीतर ही होगी।

सिक्योंग लोबसांग सांगे ने कई बार यह सुझाया है कि तिब्बत को हांगकांग जैसा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) भी बनाया जा सकता है। हालांकि, इस बारे में चीन का कहना है कि तिब्बत तो पहले से ही मुक्त है और अब इस मामले में और पीछे नहीं जाया जा सकता। हांगकांग का एसएआर का दर्जा ब्रिटेन द्वारा उसे 1 जुलाई, 1997 को हस्तांतरित करने के बाद अगले 50 साल के लिए निश्चित हो चुका है।

लातीविया के सांसदों ने दलाई लामा को आने के लिए आभार जताया और तिब्बत के प्रति अपना समर्थन दोहराया

लातीविया के रिगा में 10 सितंबर, 2013 को संसद भवन की सीढ़ियों पर वहां के सांसदों के एक समूह के साथ परमपावन दलाई लामा। फोटोः जेरेमी रसेल/ओएचएचडीएल

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 11 सितंबर, 2013)

लातीविया के दौरे के दूसरे दिन तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा से वहां के सांसद मिले और उन्होंने तिब्बत आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। परमपावन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, "हम तिब्बतियों के अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के संघर्ष का हमेशा सहयोग करेंगे। ऐसे समय में जब दुनिया में पतन हो रहा है, मूल्यों की बात करने के लिए आपका आभार। यहां आने के लिए आपका धन्यवाद और मूल्यों के महत्व को रेखांकित करने के लिए धन्यवाद।"

परमपावन ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहाः "संसद के सम्मानित सदस्यों और तिब्बत समर्थक संगठनों के लोगों, मुझे यहां आमंत्रित करने और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद। पिछले 50 साल में या उससे भी ज्यादा समय से मैं समझता हूं कि मैं कुछ हद तक यह दावा तो कर सकता हूं कि मैंने अपने समुदाय में लोकतंत्र लाने में कुछ योगदान किया है। इसके परिणास्वरूप वर्ष 2011 से मैं अपनी पूर्व राजनीतिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं। आपका अनुभव भी हमारे जैसा ही है। जब सच और बंदूक की ताकत की बात आती है तो अल्पकालिक अवधि में तो बंदूक हावी हो जाता है, लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर सच की ताकत ही जिंदा रहती है। हम चीन जनवादी गणतंत्र का हिस्सा बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि तिब्बत के आधुनिकीकरण के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, हमारी अपनी भाषा है जिससे हमें प्यार है, जैसे आपको लातिवियन से प्यार है। यह बौद्ध दर्शन की बारीकी से व्याख्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। हमारा लक्ष्य एक वास्त. विक तिब्बती स्वायत्तता की स्थापना करना है, जैसा कि चीनी संविधान में उल्लेख है। हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि वे इसे लागू करें।"

उन्होंने तिब्बती मसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। पहला है पर्यावरण का, यह विचार कि तिब्बत का महत्व एशिया के करोड़ों लोगों के जल भंडार के रूप में है। दूसरा यह कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति में करीब 40 करोड़ चीनी बौद्धों में से बहुतों की भी गहन रुचि है। तीसरा, चीन को भी न्याय और आज़ादी की जरूरत है, इसकी फिलहाल वहां कमी होने की वजह से ही वहां नैतिक दिशा सूचक का अभाव है।

चौथा, तिब्बती आंदोलन में मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी का महत्व। पांचवां, तिब्बत की स्थिति चीन और भारत के बीच एक बफर देश के रूप में जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तिब्बत में हालात को सामान्य बनाने से सैनिकों की तैनाती कम करनी होगी औ इससे पूरे क्षेत्र में संदेह का वातावरण कम होगा। इसके बाद सांसदों ने परमपावन को आमंत्रित किया कि वह लातीविया की संसद इमारत की सीढ़ियों पर सामूहिक रूप से एक फोटो खिंचाएं।

यूएनएचआरसी के सत्र में कई देशों ने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बतियों के अधिकारों का सम्मान करे

जेनेवा में 17 सितंबर को चल रहा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 24वां सत्र।

तिब्बत डॉट नेट, 19 सितंबर)

अमेरिका, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, आस्ट्रिया और ब्रिटेन सहित पांच से ज्यादा देशों ने मंगलवार को जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 24वें सत्र में चीन से यह आग्रह किया कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करे। यूरोपीय संघ ने अपने बयान में ऐसी खबरों पर चिंता जाहिर की कि चीन के खासकर तिब्बती और सीक्यांग इलाके में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जारी है और वहां फांसी की सजा का व्यापक रूप से चलन है। बयान में चीन सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह अभिव्यक्ति, सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करे। अमेरिका ने अपने बयान में कहा कि चीन ने खासकर तिब्बती और उइगर इलाके में इंटरनेट पर नियंत्रण, प्रेस पर सेंसरशिप बढ़ा दिये हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। इस बयान में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि चीन में जनहित याचिका के वकीलों, आंदोलनकारियों, पत्रकारों और धर्म गुरुओं की गिरफ्तारी, उनको जबरन गायब कर देने और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

जर्मनी ने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बत में जारी आत्मदाह की घटनाओं बुनियादी वजहों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करे। उसने चीन से यह भी अनुरोध किया कि वह तिब्बत के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त को तिब्बत के भीतर जाने देना सुलभ बनाए ताकि वहां की जमीनी सच्चाई का पता चल सके।

ब्रिटेन ने चीन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभा और प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों का चीन में पूरी तरह से संरक्षण हो, खासकर नस्लीय अल्पसंख्यकों के इलाके में। बयान में कहा गया है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल यदि मानवाधिकार परिषद में फिर से चुने जाना चाहता है तो इस बात का वचन दे कि नस्लीय अल्पसंख्यकों के कानून सम्मत अधिकारों और हितों की रक्षा की गारंटी होगी। यूएनएचआरसी के सत्र के पहले जेनेवा में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री सेतेन सामढुप छोक्यापा ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के 15 देशों के राजदूतों को ज्ञापन दिया था।

बीबीसी संवाददाता ने चीनी कब्जे वाले ल्हासा का आंखों देखा हाल बताया

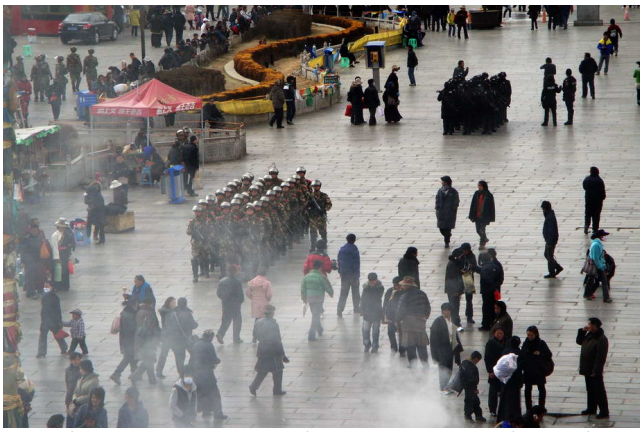

ल्हासा के परंपरागत तिब्बती बाजार में ड्रिल एक्सरसाइज करते चीनी सेना के जवान। फाइल फोटो

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 13 सितंबर)

ल्हासा में रहने वाले तिब्बती भारी प्रतिबंध से गुजर रहे हैं, उनके कहीं बाहर आने–जाने पर पूरी तरह से रोक है, जबकि शहर में हर आठ तिब्बती पर करीब एक चीनी का बसाव हो चुका है। बीबीसी संवाददाता सारा क्रूडास ने 5 सितंबर के अपने शो 'न्यू होराइजन' में यह जानकारी दी है। उनकी यह रिपोर्ट तिब्बत की इस प्राचीन शहर के दौरे पर जाकर वहां की सामाजिक दशाओं की जमीनी हकीकत देखने के बाद तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि ल्हासा की हालत देखकर वह स्तब्ध और दुःखी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि पहली नजर में देखने पर ही पता चल जाता है कि शहर वास्तव में चीनी कब्जे में है। उन्होंने कहा, "तिब्बतियों के दिन–प्रति–दिन के जीवन में काफी राजनीतिक हस्तक्षेप है। वहां से कहीं भी आज़ादी से आना–जाना मुश्किल है, देश से बाहर जाने की तो बात ही छोड़ दें। जहां भी आप जाएंगे, आपको बड़ी संख्या में सशस्त्र चीनी सैन्य कर्मी मिलेंगे, इस बात की डरावनी याद दिलाते हुए कि तिब्बत चीन के कब्जे में है। उनकी तिब्बती गाइड ने बताया कि वह विदेश जाना चाहती थी, लेकिन चीन सरकार ज्यादातर तिब्बतियों को पासपोर्ट नहीं देती। उसने बताया कि चीनी प्रशासन तिब्बतियों को संदेह की नजरों से देखती है और जगह–जगह जांच चौकियां तथा निगरानी कैमरे लगे हुए हैं।

तिब्बत में लगातार जारी आत्मदाह विरोध प्रदर्शन में दो बच्चों के पिता का निधन

दो बच्चों के पिता 41 वर्षीय शिचुंग

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 29 सितंबर, 2013)

दो बच्चों के पिता 41 वर्षीय शिचुंग की चीन शासित तिब्बत में आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद मौत हो गई है। तिब्बत में फरवरी 2009 से शुरू हुए आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन के इस सिलसिले में अब तक कम से कम 122 लोगों की मौत हो गई है। रेडियो फ्री एशिया की 28 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित गोमांग युत्सो टाउनशिप में रहने वाले शिछुंग ने अपने घर में ही खुद को आग लगा लिया और वह आग के गोले में लिपटे बाहर की ओर दौड़ पड़े। यह घटना करीब 2.30 बजे हुई, जब सिछुंग एक प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेकर लौटे थे और उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के चित्र के सामने मक्खन के दिये जलाए थे। वह आग की लपटों में ही व्यस्त सड़क पर करीब 40 कदम बढ़े और उसके बाद गिरकर दम तोड़ दिया।

चीनी पुलिस, प्रार्थना समारोह में निगरानी के लिए तैनात चीनी पुलिस तत्काल ही घटनास्थल पर आई और वह सिछुंग के झुलसे हुए शव को तिब्बतियों से छीन कर कहीं और ले गई। इस दौरान विरोध को देखते हुए पुलिस ने तिब्बतियों के ऊपर बंदूक तान रखा था। शिछुंग अपने पीछे पत्नी और 14 व 18 वर्ष के दो बच्चों को छोड़ गए हैं। शिछुंग से पहले नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के ही जोएज काउंटी के 18 वर्षीय भिक्षु कोनचोग सोनम ने गत 20 जुलाई को तिब्बत पर चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह कर लिया था और शहीद हो गए थे।

धर्मशाला के भारतीय लोगों ने तिब्बतियों के मकानों को बचाने की अपील की

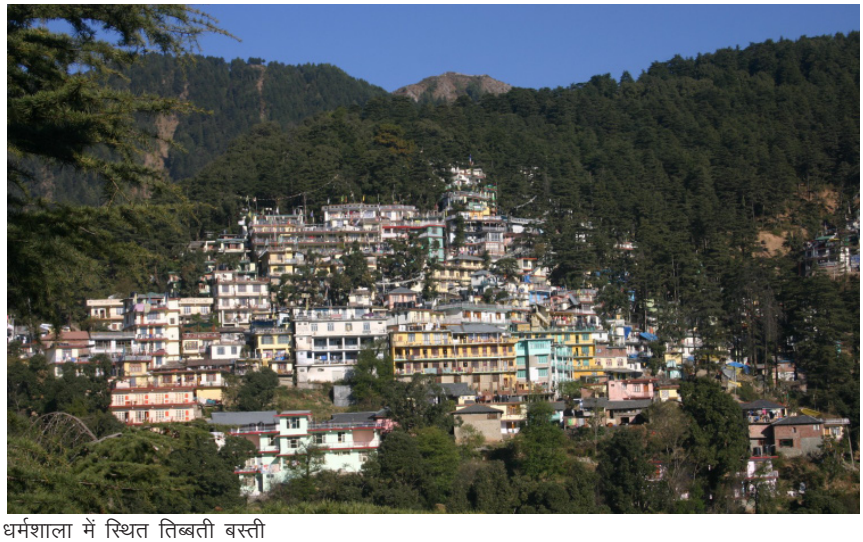

धर्मशाला में स्थित तिब्बती बस्ती

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 29 सितंबर, 2013) धर्मशाला के स्थानीय प्रशासन द्वारा तिब्बतियों के मकान ढहाए जाने के खतरे को देखते हुए स्थानीय नागरिक संगठनों ने ऐसा न करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन इन मकानों को ढहाने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट ने इस आधार पर यह आदेश दिया है कि तिब्बतियों का मकान वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण है। हकीकत यह है कि तिब्बती वहां 1960 के दशक से ही रह रहे हैं। अपील करने वाले संगठनों में भारत–तिब्बत मैत्री संघ, व्यापार मंडल, होटल एवं रेस्टोरेंट संघ, भागसू टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, ट्रेकिंग एंव माउंटेनियरिंग एसोसिएशन और अपर धर्मशाला डेवलपमेंट एसोसिएशन शामिल हैं। इन सभी संगठनों ने स्थानीय उपायुक्त को एक संयुक्त ज्ञापन देकर अनुरोध किया है मकान ढहाने के आदेश का पालन न किया जाए।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट सहित भारत की कई अदालतों ने संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर नागरिकों को भी दिए गए जीवन के अधिकार के तहत तिब्बतियों के मकानों को ढहाने से रोका था। असल में हिमाचल प्रदेश के कानून के मुताबिक राज्य के भारतीय नागरिकों के अलावा और कोई वहां जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, इसलिए तिब्बतियों को इस तरह से अस्थायी मकान बनाकर रहना पड़ता है।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने स्थानीय भारतीय समूहों से मिल रहे समर्थन की सराहना की है। तिब्बत डॉट नेट की 28 सितंबर की खबर के मुताबिक गृह मंत्री कालोन डोलमा ग्यारी ने कहा, "केंद्रीय तिब्बती प्रशासन भारतीय मित्रों द्वारा ऐसे जरूरत के वक्त दिखाई गई एकजुटता और वाजिब समर्थन के लिए काफी आभारी है।"

इस आदेश का पालन हुआ तो धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के ज्यादातर लोगों के मकान ढहा दिये जाएंगे, जबकि दलाई लामा के आवास की वजह से ही धर्मशाला एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र बन गया है।

अरुणाचल प्रदेश के नेताओं ने केंद्र सरकार से कहा कि वह तिब्बत मसले के लिए हल के लिए चीन से बात करे

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 19 सितंबर)

संवेदनशील सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश के सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आग्रह किया है कि वह तिब्बत के साथ एकजुटता दिखाएं और इस मसले के सकारात्मक समाधान के लिए चीन के साथ तत्काल बातचीत शुरू करें। पीटीआई की खबर के मुताबिक 17 सितंबर को प्रधानमंत्री को दिये एक ज्ञापन में नेताओं ने यह आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि तिब्बती जनता के अनुकूल एक स्थायी समाधान निकालना भारत और एशिया के सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।

इस ज्ञापन में कहा गया है, "परंपरागत रूप से अरुणाचल प्रदेश का आज़ाद तिब्बत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता था और दोनों इलाकों के बीच व्यापार चलता था। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तिब्बती जनता के साथ सहानुभूति और एकजुटता रही है।"

सीमावर्ती राज्य के नेताओं ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह तिब्बत मसले का हल निकालने के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता को प्रोत्साहित करे। वह यह भी चाहते थे कि चीन पर इस बात के लिए दबाव बनाया जाए कि वह तिब्बती जनता के मानवाधिकारों का सम्मान करे और उनके धर्म, संस्कृति, भाषा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करे।

इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष मुकुट मिथी, एनसीपी के राज्य अध्यक्ष काहफा बेंगिया, भाजपा के राज्य अध्यक्ष ताई तगाक, अरुणाचल प्रदेश पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कामेंग रिंगकू और अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष टाचो कबाक शामिल थे।

निर्वासित तिब्बती संसद ने भारतीय सांसद और तिब्बत समर्थक मोहन सिंह के निधन पर शोक जताया

मोहन सिंह वर्श 1968-69 में इलाहाबाद वि वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की भ्ाुरुआत हुई। वह भारतीय समाजवादी आंदोलन के जनक राजनरायण और राम मनोहर लोहिया से प्रेरित थे।

Jh ekgu flag

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 24 सिंतबर)

तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने गत 22 सितंबर को श्री मोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख जताया है। भारतीय संसद के उत्कृष्ट सांसद रहे श्री मोहन सिंह लंबे समय से तिब्बतियो के संघर्ष के सहयोगी थे। समाजवादी नेता और भारत की समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री सिंह को वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवॉर्ड दिया गया था और वे वर्ष 1979–80 में उत्तर प्रदेश मे मंत्री भी रहे थे।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन के नेता सिक्योंग लोबसांग सांगे ने 23 सितंबर को कहा कि दलाई लामा ने श्री सिंह के निध न की खबर सुनकर गहरा शोक जताया है और उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। सिक्योंग ने खुद सिंह के निधन पर शोक जताते हुए इसे "एक सच्चे मित्र की क्षति" बताया और उन्हें "उच्च सिद्धांतों वाला व्यक्ति" बताया।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर 23 सितंबर को प्रकाशित खबर के मुताबिक सिंह ने कहा, "श्री मोहन सिंह तिब्बत के लंबे समय से मित्र रहे हैं। उन्होंने तिब्बत पर सर्वदलीय भारतीय सांसदों के मंच (एपीआईपीटी) के संयोजक के रूप में और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।"

इसके अलावा धर्मशाला स्थित तिब्बती प्रशासन ने 23 सितंबर को ही एक प्रस्ताव पारित कर श्री सिंह के निधन पर शोक जताया। यह याद किया गया कि नई दिल्ली में 1994 में तिब्बत पर पहले विश्व सांसद सम्मेलन आयोजित करने में उन्होंने श्री जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर शीर्ष भूमिका निभाई थी।

68 वर्षीय श्री सिंह का 22 सितंबर को अपराह्न 4.15 बजे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गांव जयनगर में रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे थे और उनका जन्म 1945 में हुआ था। मोहन सिंह वर्ष 1968–69 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। वह भारतीय समाजवादी आंदोलन के जनक राजनरायण और राम मनोहर लोहिया से प्रेरित थे। वह आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे। इसके पहले भी कई बार धरना, प्रदर्शनों के दौरान सिंह को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। एक बार 1966 में ऐसा हुआ था जब वह एक आंदोलन के तहत इलाहाबाद के आनंद भवन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पुराने समाजवादी नेता और मधु लिमये के दोस्त मोहन सिंह तीन बार देवरिया से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उन्हें एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। वह सत्तर के दशक में उत्तर प्रदेश के विधायक थे। सिंह अपने राजनीतिक करियर के दौरान लोकदल, जनता पार्टी और समता पार्टी से भी जुड़े रहे।

पुस्तकों में रुचि रखने वाले सिंह एक अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने खुद कई किताबें लिखीं, जिनमें 'भारतीय संविधान के निर्माण में नेहरू', 'भारतीय लोकतंत्र का संकट', 'समाजवादी आंदोलन का इतिहास', 'डॉ. अम्बेडकर–अ मल्टीफेसेटेड पर्सनॉलिटी' और 'फ्रीडम मूवमेंट ऐंड सोशलिस्ट कंट्रिब्यूशन" प्रमुख हैं।

निर्वासित तिब्बती संसद ने 23 सितंबर, 2013 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर वरिष्ठ नेता और तिब्बत आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे श्री मोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख जताया है।

स्विट्जरलैंड के फ्रिबोर्ग में 13 अप्रैल 2013 को स्वर्गीय रॉबर्ट फोर्ड (1923–2013) को मरणोपरांत इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत के लाइट ऑफ ट्रुथ अवॉर्ड देते परमपावन दलाई लामा। फोटोः मैनुअल बॉअर रॉबर्ट

आज़ाद तिब्बत के पहले विदेशी कर्मचारी का निधन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 26 सितंबर)

आज़ाद तिब्बत सरकार द्वारा 1940 के दशक में रेडियो अधिकारी नियुक्त किए गए ब्रिटिश नागरिक रॉबर्ट फोर्ड को 90 वर्ष की अवस्था में 20 सितंबर, 2013 को लंदन में निधन हो गया। वाशिंगटन स्थित संगठन इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत ने इस साल अप्रैल में उन्हें लाइट ऑफ ट्रुथ अवॉर्ड दिया था। उन्होंने परमपावन दलाई लामा से स्विट्जरलैंड के फारिबोर्ग में यह अवॉर्ड हासिल किया था।

रॉबर्ट फोर्ड ने 1940 के दशक में राजधानी ल्हासा और पूर्वी तिब्बम के खम प्रांत स्थित मुख्य शहर चामदो में रेडियो अधिकारी के रूप में काम किया था। उन्हें तिब्बत के पहले प्रसारण स्टेशन स्थापित करने और तिब्बती रेडियो ऑपरेटर को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

1950 के दशक में एक भूकंप आने से उनके लिए भागने का रास्ता बंद हो गया और तिब्बत पर कब्जा कर चुकी चीन की जनमुक्ति सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें करीब पांच साल तक चीन में कैद रखा गया। इसमें से तीन साल वह छोंगक्विंग में थे, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जाती रही और उनको फांसी दिए जाने का डर हमेशा बना रहा। चार साल कैद में रखने के बाद आखिरकार चीनियों ने उनकी मां को पत्र लिखकर बताया कि वह जिंदा हैं। चीन ने 1954 में उन्हें जासूसी के आरोप में दस साल जेल की सजा सुनाई, लेकिन 1955 में ही उन्हें रिहाकर देश से बाहर निकाल दिया गया। 27 मार्च, 1923 को ब्रिटेन के स्टैफोर्डशायर में जन्मे फोर्ड ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत और इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स में रेडियो टेक्निशियन के रूप में काम किया था। वर्ष 1945 में उन्होंने ल्हासा के ब्रिटिश मिशन में रेडियो अधिकारी के रूप में काम किया। वर्ष 1945 में फोर्ड का स्थानांतरण सिक्किम के शहर गांतोक के राजनीतिक कार्यालय में कर दिया गया था। वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद वह तिब्बत लौट गए और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगे रहे।

तिब्बत सरकार ने उन्हें अपनी सेवा में शामिल होने का ऑफर दिया और तिब्बत में पहला प्रसारण स्टेशन स्थापित करने, तिब्बती रेडियो ऑपरेटर को प्रशिक्षित करने और पूरे तिब्बत में रेडियो संचार नेटवर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। वह ऐसे पहले पश्चिमी नागरिक थे जिन्हें आज़ाद तिब्बत की

सरकार ने अपना कर्मचारी बनाया और उन्हें अधिकारी का ओ. हदा दिया। उन्होंने रेडियो ल्हासा के तैयार होने और उद्घाटन में उनका पूरा योगदान रहा और इस तरह से तिब्बत पहली बार बाहरी दुनिया तक प्रसारण करने लगा। एक साल तिब्बत की राजधानी में रहने के बाद फोर्ड से चामदो जाने और वहां भी तिब्बती रेडियो के संचार नेटवर्क के विस्तार करने का काम सौंपा गया। उनकी पुस्तक 'कैप्चर्ड इन तिब्बत' का 1957 में प्रकाशन हुआ था और इसमें कम्युनिस्ट चीन के कब्जे के बाद तिब्बत के जीवन की व्यापक झलक मिलती है। वर्ष 1957 में फोर्ड ने ब्रिटिश डिप्लोमेटिक सर्विस ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने लंदन के विदेश कार्यालय और दुनिया के कई अन्य देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका, मोरक्को, अंगोला, फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड स्थित ब्रिटिश दूतावासों या वाणिज्य दूतावास में काम किया। वर्ष 1983 में वह स्विट्जरलैंड से रिटायर हो गए। वर्ष 1982 में श्री फोर्ड को कमांडर ऑफ दि ऑर्डर ऑफ दि ब्रिटिश एम्पायर का अवॉर्ड दिया गया। फोर्ड ने 1956 में अपने एक बचपन के दोस्त से शादी की जो उनसे न्यूयॉर्क में दुबारा मिलीं थी जहां वह संयुक्त राष्ट्र में काम कर रही थीं। फोर्ड लंदन में 1959 में स्थापित तिब्बत सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और अपने शेष जीवनभर वह इसके उपाध्यक्ष बने रहे। उन्होंने तिब्बत एवं चीन पर गहनता से लिखा और इस पर ब्रिटेन, यूरोप के अन्य हिस्सों, आस्ट्रेलिया, अमेरिका में कई व्याख्यान दिए।

वर्ष 1996 में फोर्ड ने दलाई लामा और ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी क्वीन मदर से क्लीयरेंस हाउस में मुलाकात करवाई। फोर्ड अपने पीछे अपने दो बच्चे और तीन पोते–पोती छोड़ गए हैं। लाइट ऑफ ट्रुथ अवॉर्ड समारोह के दौरान फोर्ड ने कहा था: "मैं पश्चिमी नागरिकों के उस विशिष्ट क्लब का हिस्सा हूं जिनको 1950 से पहले आज़ाद तिब्बत को देखने, जानने और उसका गवाह बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने तिब्बत में अपने जीवन के कुछ बेहद खुशनुमा दिन गुजारे थे। मैं 1945 में जिस तिब्बत में रहता था, वह आज के तिब्बत से काफी अलग था। यह एक आज़ाद देश था जिसकी अपनी सरकार, अपनी भाषा, संस्कृति, रीति–रिवाज और जीवन जीने का तरीका था।"

निर्वासित तिब्बती संसद ने 27 सितंबर, 2013 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर गादेन फोड्रांग तिब्बती सरकार द्वारा नियुक्त पहले विदेशी कर्मचारी और तिब्बत आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे श्री रॉबर्ट डब्ल्यू फोर्ड के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त किया।

रॉबर्ट फोर्ड कई तिब्बती अधिकारियों के साथ 1950 में चीनी सेना द्वारा पकड़े गए थे और उन्हें 5 साल जेल में बिताना पड़ा था।

दलाई लामा का जन्म दिन मना रहे तिब्बतियों को चीनी सैनिकों ने गोलियों से भूना

चीनी सैनिकों ने पूर्व तिब्बती के ताउ में दलाई लामा का जन्म दिन मना रहे तिब्बतियों पर धावा बोल दिया, इससे साबित होता है कि अब भी चीन की मुख्य नीति दमन की ही है।

केट सांडर्स, इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत में संचार निदेशक

(केट सांडर्स, द संडे गार्जियन, 1 सितंबर, 2013)

हाल में लद्दाख में ध्यान शुरू करने वाले दलाई लामा 6 जुलाई को 78 वर्ष के हो गए। लेकिन अपनी जन्मभूमि में उनका जन्म दिन खुले में मनाने के खतरे को जानते हुए भी तमाम तिब्बतियों ने चुपचाप जुटकर उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। चीनी प्रशासन इसके सख्त खिलाफ रहता है और इससे उसे लगता है कि लोगों पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो रहा है।

पूर्वी तिब्बत के एक इलाके ताउ में इस बात की लोगों को तीव्र याद दिलाई गई कि अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का साहस करना कितना जोखिमभरा हो सकता है। एक पवित्र पर्वत की ढलान में बैठ तिब्बती दलाई लामा का जन्मदिन काफी परंपरागत तरीके से मना रहे थे, पिकनिक मनाने, दलाई लामा की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाने, उस पर सफेद कपड़ा बांधने आदि के द्व ारा। लेकिन तब ही चीनी सुरक्षा बल आए और इस उत्सव को देखकर काफी नाराज हुए। कुछ तिब्बती कार में बैठकर भागने की कोशिश करने लगे तो गुस्साई पुलिस ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। वरिष्ठ भिक्षुओं ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। एक तस्वीर में स्थिति पूरी तरह से बयां हो रही है, जिसमें तिब्बती भिक्षु, मर्द, औरतें और बच्चे पेडों के नीचे जड़वत बैठे हुए हैं और स्वचालित हथियारों, ढाल से लैस विशेष सुरक्षा बल एवं पुलिस के जवान उनको घेरे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बल गोलीबारी शुरू कर देते हैं।

तिब्बत से बाहर गुप्त रूप से भेजी गई ऐसी ही एक तस्वीर में एक भिक्षु के सिर में घाव दिख रहा है, उनकी खोपड़ी में पूरा सुराख बन गया है। एक और तस्वीर में एक व्यक्ति के पीठ पर बड़ा कुरूप सा घाव है, ऐसा लगता है कि उसे काफी करीब से गोली मारी गई है। इस घटना में कम से कम दस तिब्बती गंभीर रूप से घायल हुए और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा कि वे जिंदा हैं भी या नहीं। इनमें से एक ताउ के उन तिब्बती भिक्षुणी का छोटो भाई था, जिनकी हाल में आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई थी। तिब्बत में आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन की वर्ष 2009 से ही लहर चल रही है।

दुनिया भर में अहिंसा अभियान का नेतृत्व करने वाले एक सम्मानित धार्मिक हस्ती का जन्म दिन मनाने के लिए जुटे लोगों का यह एक भयावह अंत था। ऐसे तो पहले से भी कई उदाहरण थे कि चीनी सैनिकों ने निहत्थे तिब्बतियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी हो, लेकिन यह आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान होता था, अब तो यह शांतिपूर्ण तरीके से पिकनिक मना रहे लोगों पर भी शुरू कर दिया गया है। यदि 6 जुलाई को ताउ में फायरिंग का निर्णय स्थानीय सैनिकों ने ऊपर के आदेश के बिना लिया हो तो भी इससे तिब्बत में चल रहे दमन की खतरनाक संस्कृति तो उजागर हो ही जाती है। असल में तिब्बती सैनिकों के उस कमांडर का नाम बताने में हिचक रहे हैं जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, क्योंकि वह तिब्बती था। इससे मुझे तिब्बती लेखिका वुएजर द्वारा बताई गई एक कहानी याद आती है। जब बर्लिन की दीवार ढह गई तो पूर्वी जर्मनी के एक पूर्व सैनिक ने , जिसने दीवार पर चढ़ने वाले एक व्यक्ति को गोली मारी थी, अदालत में अपने बचाव में कहा कि वह तो ऊपर के आदेश का पालन करने वाला एक सैनिक मात्र ही है। लेकिन इसके बावजूद उसे जज ने सजा दी। जज ने टिप्पणी की कि उनके वरिष्ठों ने यह तो नहीं कहा था कि अपनी बंदूक को एक सेंटीमीटर भी ऊपर की ओर न करना। वुएजर लिखती हैं: "इस कहानी से यह पता चलता है कि एक दमनकारी एकतंत्रीय व्यवस्था में भी खुद को और अपने हितों को बचाने की कोशिश करने वाले व्यवस्था के लोग अपनी जमीर को परे नहीं रख सकते।"

हाल के हफ्तों में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ अधिकारी तिब्बत में नया रवैया अपनाने की संभावना तलाश रहे हैं। शीर्ष नेता अपने सार्वजनिक बयानों में कठोर रुख बनाए हुए हैं जिससे यह संकेत मिल रहा है कि दलाई लामा विरोधी अभियान अब भी उनकी तिब्बत नीति का मुख्य हिस्साा है। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि चीन और तिब्बत में कुछ चालाकी भरी और कम आक्रामक नीति अपनाने पर विचार चल रहा है। इससे कुछ उम्मीद बनती है, भले ही नाजुक सी, कि कुछ तिब्बती इलाकों में इस साल दलाई लामा के जन्मदिन मनाने की इजाजत दी गई है, ताउ जैसे किसी दमन के बिना। बीजिंग के एक प्रभावी विद्वान प्रोफेसर जिन वी ने हाल में पार्टी से आह्वान किया है कि दलाई लामा से संपर्क साधा जाए और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि तिब्बतियों की वास्तविक शिकायतों का समाध ाान किया जाए। इस बीच, पूर्वी तिब्बत के कुछ इलाकों में तिब्बतियों की कुछ बैठकों में

दलाई लामा की तस्वीर रखने की इजाजत दी गई और तिब्बतियों को अपने धार्मिक नेता की निंदा करने को मजबूर नहीं किया गया। अब भी बहुत जगहों पर तिब्बतियों को दलाई लामा की निंदा करने को मजबूर किया जाता है जिसे तिब्बती "दिल में छूरी चलाना" मानते हैं।

हालांकि, जमीनी स्तर पर किसी ठोस बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। प्रगतिशील चीनी विद्वान और वकीलों ने "स्थिरता बनाए रखने के रवैये" की आलोचना की है। इसके तहत चीन के पुलिस और सैन्य दस्तों, साजो–सामान में भारी विस्तार किया गया है और पूरे चीन में एक पार्टी शासन के किसी तरह के विरोध को कुचल दिया जाता है। चीन की राजनीतिक भाषा में "स्थिरता" किसी भी तरह की "सामाजिक असंतोष" को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कूट संदर्भ है। चीन के तिब्बती इलाकों में तो "स्थिरता बनाए रखने" की नीति को युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है।

बहुत कम चीनी यह जानते हैं कि तिब्बती इलाकों में "सुरक्षा" के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। इसे काफी गोपनीय तरीके से छुपाकर रखा जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सरकारी खजाने पर एक भारी बोझ है। धर्मशाला स्थित एक एनजीओ तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) द्वारा हाल में प्रकाशित एक दुर्लभ आंतरिक दस्तावेज से पता चलता है कि तिब्बत में दमन में लगी चीनी सशस्त्र पुलिस भी सुरक्षा बलों के बार–बार निर्दयी प्रतिक्रिया से परेशान है और इससे उनमें लंबे समय के लिए मानसिक परेशानी कायम हो सकती है।"

तिब्बत में तैनात सुरक्षा कर्मियों के एक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य मैनुअल से पता चलता है कि चीन सरकार खुद को तिब्बत में लंबे समय से आतंकवाद से निपटने में लगी बता रही है। ताउ में दलाई लामा के जन्मदिन के उदाहरण से जैसा कि दिखता है, यह किसी भी सशस्त्र आतंकवाद या चीनी सुरक्षाकर्मियों या नागरिकों के ऊपर किसी तरह के खतरे के बावजूद हो रहा है।

(केट सांडर्स, इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत में संचार निदेशक हैं)

भारत का एलएसी, चीन का फायदा

बीजिंग सीमा पार अपनी रेखा खींच रहा है, भारत इसे ई वर की इच्छा मानकर संतोश कर रहा है

पी.के. वासुदेव

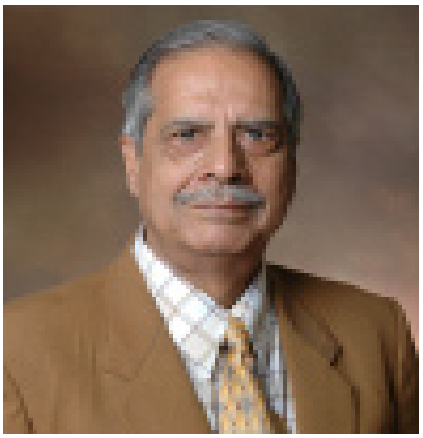

(डेली पोस्ट, 17 सितंबर)

भारत–चीन सीमा मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की एक रिपोर्ट ने सरकारी आशंका की पुष्टि की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के चेयरमैन श्याम शरण द्वारा 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी गई गई वास्तविक हालात की रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) के जवान पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त नहीं करने दे रहे। हालांकि, सरकार ने इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन शरण ने संकेत दिया है कि "गश्त की सीमाएं" लद्दाख सेक्टर के कई इलाकों में नई एलएसी बन गई है। इस तरह चीन ने भारतीय इलाके के करीब 640 वर्ग किमी. क्षेत्र को चीन ने दबा लिया है।

प्रधानमंत्री ने शरण से कहा था कि वह 2 से 9 अगस्त तक पूर्वी लद्दाख और सियाचिन सेक्टर का दौर कर सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्य और एलएसी के हालात की समीक्षा करें। इसके पहले मई 2007 मे इसी तरह की कवायद कर चुके शरण ने दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सेक्टर, देपसांग बल्गे और चुमार सेक्टर में चीनी अतिक्रमण के गंभीर हालात की रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) को भी सौंपी गई है। बताया जाता है कि गृह सचिव अनिल गोस्वामी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति बनाई गई है जो एलएसी के हालत पर निगरानी रखेगी और कैबिनेट सचिव अजित सेठ की अध्यक्षता वाले मौजूदा सीमा बुनियादी ढांचा विकास पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से कहा गया है कि वह लद्दाख में अफसरशाही की अड़चनों को दूर करे।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की भारतीय अवधारणा, जिसे कि 1962 के युद्ध में नियंत्रण के आधार पर 1976 में चाइना स्टडी ग्रुप (सीएसजी) ने तैयार किय था, अब कम से कम डीबीओ से लेकर चुमार तक 12 इलाकों में चीनियों की धारणा से काफी अलग है।

हालांकि, विदेश, गृह, रक्षा सचिवों, सेना के उप प्रमुख और खुफिया संगठनों के प्रमुखों वाली चीन की सीएसजी ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के "निगरानी के लिए सीमा" तय कर दी है। यह गश्त रेखा असल में भारत और चीन के एलएसी की धारण ाा के बीच में है और यह भारतीय सीमा में 2 से 20 किमी. की कटौती करती है। शरण ने रिपोर्ट दी कि चीनियों ने डीबीओ सेक्टर के संवेदनशील ट्रैक जंक्शन एरिया में गाड़ियों के चलने लायक 'कच्चा' रोड बना लिया है, इस तरह जमीनी स्तर पर सीमा की स्थिति बदल रही है और यह 2005 के प्रोटोक. ॉल का उल्लंघन है। शरण और उत्तरी क्षेत्र के पूर्व आर्मी कमांडर ले.जनरल पी.

सी. भारद्वाज ने पानगोंग सो का भी सर्वे किया जो एलएएसी से गुजरने वाली नमकीन पानी की झील है। उन्हें पता लगा कि और मजबूत हो चुकी पीएलए ने सृजप इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। शरण ने चुमार की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की जहां पीएलए लगातार अतिक्रमण करती रही है और दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के परिभाषित होने के बावजूद उसने 85 किमी. भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा किया है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने संसद के दोनों सदनों में इन खबरों को खारिज किया है जिनमें यह आरा.`प लगाया गया था कि जम्मू–कश्मीर के लद्दाख इलाके में चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्हा.`ने कहा कि चीन को जमीन सौंप देने का कोई सवाल ही नहीं है और भारत सरकार चीन से इस बारे में बात कर रही है कि सीमा मसले को हल करने के लिए ज्यादा प्रभावी तंत्र बनाया जाए। उन्होंने साफतौर से इस बात से इनकार किया कि श्याम शरण ने पीएमओ को दी गई रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या वह भारतीय सीमा के हिस्से में भारतीय सैनिकों को नहीं जाने दे रहा। उन्हा.`ने कहा, "सरकार सभी घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है और भारत की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।"

हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया था कि सीमा पर दोनों सेनाएं आमने–सामने हुई थीं और चीन को यह डर है कि भारत उसके मुकाबले अपनी क्षमताएं मजबूत कर रहा है। हालांकि, उन्होंने संसद सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार सीमा पर भारतीय क्षमताओं को मजबूत करती रहेगी। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि सीमा पर क्षमताओं को मजबूत करने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीन ने अपनी क्षमता विकसित कर ली है। देर से ही सही भारत अब इस मामले में चीन से बराबरी करने की ओर बढ़ रहा है। सीमा पर अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए और बातचीत से कोई रास्ता निकालने के लिए राजनयिक स्तर पर भी चीन से संपर्क जारी रखते हुए भारत का लक्ष्य यह है कि सीमा पर शांति और सौहार्द को बनाए रखा जाए। एंटनी ने कहा कि शरण की रिपोर्ट लद्दाख इलाके में हवाई सुविधाओं के विकास की जरूरत पर बल देती है और यह भी बताती है कि इसके लिए जमीन अधि ाग्रहण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी जैसे मसले आएंगे। उन्हा.`ने कहा, "स्थानीय युवकों को रोजगार, पर्यटन, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कानून–व्यवस्था, बेहतर साजो–सामान, आईटीबीपी के लिए सुविधाएं, स्थानीय जनता की कुछ समस्याओं का समाध ाान जैसे कई मसलों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।"

विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर बयान जारी करने की मांग करते हुए कहाः "यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मसला है।" विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार चीन के प्रति कमजोर रक्षा नीति अपना रही है और उन्हा.`ने जोर दिया कि ऐसे अतिक्रमण का सामना करने के मामले में सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। शरण और जनरल भारद्वाज ने हालांकि, ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जिसे 1990 के दशक से अब तक सरकार को पता न हो। इसके लिए प्रधानमंत्री को कोई कोई तथ्यान्वेषी दल भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेना तो हर दिन–प्रति दिन अतिक्रमण की जानकारी देती रहती है। सच तो यह है कि सेना को भारत के मुताबिक तय एलएसी पर निगरानी करने की इजाजत नहीं मिल रही। जबकि 1962 के बाद यह दोनों देशों के बीच यह आपसी सहमति से तय सीमा है। अभी सेना की गश्त रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा निध ार्रित एक लाइन तक ही हो पा रही है। दूसरी तरफ, चीन की तरफ गश्त उसके बॉर्डर गॉर्ड रेजिमेंट द्वारा की जा रही है। फर्क यह है कि आईटीबीपी के विप. रीत यह यूनिट चीनी सेना का अंग है और इसमें नियमित सैनिक शामिल हैं, पुलिस के लोग नहीं। निगरानी की यह रेखा एलएसी के भारतीय संस्करण से 15 से 20 किमी. पीछे है। अब यह पता नहीं है कि आईटीबीपी उस जगह पर गश्त कर पा रही है कि नहीं, जहां वह 1990 के दशक में किया करती थी, तब जबकि ऐसे मामलों में सेना की ज्यादा चलती थी। आईटीबीपी को इसलिए सेना के सीधे संचालनात्मक कमान के तहत लाना होगा, जैसे कि चीनी गॉर्ड्स हैं। इसकी वजह से चीन जबर्दस्ती अपने को धीरे–धीरे फैलाता जा रहा है और निगरानी रेखा एलएसी बनती जा रही हैं। यहां तक कि सेना या आईटीबीपी के अधिकारियों भी चीन द्वारा धीरे–धीरे भारतीय जमीन कब्जाने या उसकी सोच का पता ही नहीं है। शीर्ष नीतिगत स्तर पर तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इस मसले की कोई चर्चा नहीं की जा रही और मूल रूप से जनता में घबराहट पैदा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। एलएसी पर नियंत्रण से सेना को दूर रखा जा रहा है और जनता पूरी तरह से अंधेरे में है। परिस्थितियों की वजह से पिछले दो दशकों में अपने को कमजोर स्थिति में डाल चुकी भारत सरकार के पास इतना साहस नहीं है कि वह परस्थिति से निपटने के लिए वह एलएसी पर धीरे–धीरे अपनी गश्त रेखा बढ़ाए जैसा कि स्थानीय सैन्य कमांडरों ने सिफारिश की है। यह भी एक पहेली है कि पीएलए किस तरह से भारतीय सैनिकों को एलएसी पर निग. रानी करने से रोक रही है या इसकी इजाजत नहीं दे रही है। साफ है कि भारत सरकार अपनी पिछली कायरता छिपाने का प्रयास कर रही है।

हम यह सुझाव नहीं दे रहे कि लड़ाई ही कर ली जाए, लेकिन भौतिक एवं राजनयिक समाधान की कोशिश से ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। यह अचरज की बात है कि देश के इतने विश्वसनीय नेता इतने भोले कैसे हो सकते हैं।

भारत ने चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मोड़ने को छोटी बात बताया

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ब्रह्मपुत्र की तीन सहायक नदियों में चीन से आने वाले जल का योगदान सिर्फ ७ फीसदी का है

(लाइवमिंट डॉट कॉम, नई दिल्ली, 9 सितंबर) ब्रह्मपुत्र की धाराएं चीन द्वारा मोड़ने को भारत हल्के में ले रहा है, जबकि एक विश्लेषक ने भारत सरकार के इस रवैये की आलोचना की है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ब्रह्मपुत्र की चीन से निकलने वाली तीन सहायक नदियों–सुबानसिरी, सियांग और लोहित में चीन से आने वाली धाराओं का योगदान महज 7 फीसदी है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, "ब्रह्मपुत्र की पांच बड़ी सहायक नदियों में सिर्फ तीन चीन से आती हैं और बाकी अरुणाचल प्रदेश से। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र में आने वाले कुल जल में चीन से आने वाली जलधाराओं का योगदान महज 7 फीसदी है। इसमें चीनी क्या कर सकते हैं? वे कितनी धारा मोड़ सकते हैं?"

भारत के जल संसाधन और ऊर्जा मत्रालयों ने चीन में बनने वाली 62 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना पर आपत्ति जताई है जिसके द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर जलधाराओं को मोड़ा जाना है। इस पर काफी समय तक हो–हल्ला मचाने के बाद ऐसा लगता है कि अब भारत सरकार अपने रवैए को नरम बना रही है। एक और अधिकारी ने कहा, "ऊपरी इलाके में बहुत ज्यादा जल इकट्ठा नहीं होता है।" यह दूसरे व्यक्ति चीन के जलधाराओं को मोड़ने की योजना पर भारत के सामरिक जवाब तैयार करने में शामिल रहे हैं और यह भी अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते।

ब्रह्मपुत्र नदी की 2,880 किमी. लंबाई में से 1,625 किमी. तिब्बत में, 918 किमी. भारत में और 337 किमी. बांग्लादेश में बहती है। भारत के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार इस इसके कुल 5,80,000 वर्ग किमी. बहाव क्षेत्र में से 50 फीसदी तिब्बत में, 34 फीसदी भारत में और शेष बांग्लादेश व भूटान में। तिब्बत में औसत सालाना वर्षा 400 मिमी. और भारत में बहने वाले ब्रह्मपुत्र इलाके में 3,000 मिमी. की बारिश होती है। इसलिए विश्लेषक 7 फीसदी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं. दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, "हर तरह के फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। यह आंकड़े बदलते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र बहुत विशिष्ट नदी है। इसके बारे में प्रमाणिक आंकड़े सिर्फ संयुक्त राष्ट्र से मिलते हैं। जनता को गुमराह करने के लिए भारत सरकार सही आंकड़े जारी नहीं करती।

भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युतपरियोजनाओं पर झगड़ते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है और भारत में जल विद्युत उत्पादन की सबसे ज्यादा क्षमता इसी राज्य में है। चीन ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलने वाली सहायक नदियों की धारा मोड़कर उन्हें शीक्यांग और गांसू के शुष्क इलाकों तक पहुंचाना चाहता है। इससे भारत को अरुणाचल में बनने वाली अपनी जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर चिंता हो गई है। दूसरी तरफ, नई दिल्ली अपनी इन परियोजनों का काम धीमी गति से चलने को लेकर भी चिंतित है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार ब्रह्मपुत्र में 60 फीसदी जल भारत से और 40 फीसदी जल तिब्बत से आता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर करीब 15,000 से 20,000 मेगावॉट तक जलविद्युत उत्पादन की क्षमता है। इस इलाके में पनबिजली परियोजनाओं को लागू करने में देरी, खासकर चीन से निकलने वाली नदियों पर, पहले इस्तेमाल के भारत के दावे को कमजोर करेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक दूसरे देशों के साथ साझे वाले प्राकृतिक संसाधनों पर किसी देश का दावा मजबूत हो जाता है, यदि वह पहले से उनका इस्तेमाल कर रहा हो।

मिंट अखबार ने 29 अगस्त को इस बारे में खबर दी है कि केंद्र सरकार इस इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य तेज करने का प्रयास कर रही है जिसे कि पहले नजरअंदाज किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था में सीमा पार वार्षिक कुल जल प्रवाह 165.4 अरब क्यूबिक मीटर होता है, जो कि तिब्बत पठार से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बहने वाली तीन प्रमुख नदियों मेकांग, सालवीन और इरावदी में कुल मिलाकर बहने वाले जल से भी ज्यादा है। ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि ऊपरी जल धारा से असल में नदी में पोषक बहुल गाद भी आते हैं। चेलानी ने कहा, "एक बार यदि चीनी ब्रह्मपुत्र की धारा में 30 फीसदी की कमी ला देंगे तो इससे पूरे नदी पारिस्थिति तंत्र का बहाव शिथिल पड़ जाएगा। निचले जल धारा में जुटने वाला जल संग्रह इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसी काम का नहीं है। किसी को भी जल के मामले में व्यापक रवैया अपनाना चाहिए, बजाय इसको विभिन्न मंत्रालयों में लटकाने के।"

भारत के पास कुल 2,25,794 मेगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता है जिसमें से 17.55 फीसदी या 39,623.40 मेगावॉट पनबिजली होती है। देश में सबसे ज्यादा पनबिजली उत्पादन क्षमता अरुणाचल प्रदेश में ही है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 90,000 वर्ग किमी. जमीन उसकी है और उसने जम्मू–कश्मीर में करीब 38,000 भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। चीन–पाकिस्तान में मार्च 1963 में हुए सीमा समझौते के बाद पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का 5,180 वर्ग किमी. भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया।

चीन का लगातार जारी अतिक्रमण

अब समय आ गया है कि भारत सरकार एक भवेतपत्र प्रकाि ात करे और भारतीय जनता को यह बताए कि क्या हो रहा है। नेहरू लगातार भवेतपत्र जारी किया करते थे (वर्श १९५९ और १९६५ के बीच १५ भवेतपत्र जारी किए गए)। मौजूदा सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? किसी भी तरह से यह समझदारी भरा कदम होगा, इसके पहले कि कुछ बाबू लोग प्रासंगिक फाइल को गायब कर दें।

(द स्टेट्समैन, 14 सितंबर)

पांचवीं भारत–चीन सामरिक वार्ता हाल में दिल्ली में आयोजित की गई। कहा जा रहा है कि इसमें चीन के पक्ष में लगातार बढ़ते जा रहे व्यापारिक असंतुलन को कम करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सीमा के मसले और ब्रह्मपुत्र जैसी सीमा पार तक बहने वाली नदियों के लिए किसी संभावित गठजोड़ के मामले में वह अपनी पोजीशन पर अड़ा रहा है।

इस बैठक के बाद बताया गया कि "दोनों पक्षों ने हाल के द्विपक्षीय व्यवस्था सीमा पर कार्य प्रणाली (2012) में भरोसा जताया है।" लेकिन इससे भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों का अतिक्रमण नहीं रुका है।" नई विदेश सचिव सुजाता सिंह और उनके चीनी समकक्ष उप विदेश मंत्री लिउ झेनमिन (जो कई साल तक विदेश मंत्रालय के समझौता एवं कानून विभाग में महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं) चाहते थे कि नए सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते (बीडीसीए) को मान्यता दिया जाए। ऐसे समय में जब चीन लगातार वास्तवकि नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई नया समझौता 1993, 1996, 2005 और 2012 में हुए समझौतों से ज्यादा प्रभावी साबित होगा। इसलिए किसी को भी जिज्ञासा हो सकती है, आखिर क्यों नया बीडीसीए? यह सिर्फ अक्टूबर में प्रधानमंत्री के बीजिंग दौरे का औचित्य सिद्ध करने का एक छलावा ही है। लेकिन आखिर पीएमओ के बाबू कोई बेहतर बहाना या वजह क्यों नहीं तलाशते?

पिछले कई महीनों से मीडिया लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों द्वारा कई जगह अतिक्रमण की लगातार खबरें आती रही हैं, चाहे वह दौलत बेग ओल्डी के निकट हो, श्री जाप, चुमार या देमचोक के निकट। ऐसा लगता है कि चीनियों ने अपना अतिक्रमण अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित कर दिया है, खासकर अंजवा जिले तक। बीजेपी के पूर्व सांसद तापिर गावो ने दावा किया है कि पिछले महीने चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) कम से कम नौ भारतीय सीमा चौकियों को बर्बाद करते हुए भारतीय सीमा में 30 से 40 किलोमीटर भीतर तक घुस आई थी। गावो ने पुष्टि की है कि मैकमोहन रेखा पर अभी भी सैनिक आमने–सामने डटे हुए हैं। असम ट्रिब्यून से बात करते हुए तापिर गावो ने यह दोहराया कि यह अतिक्रमण करीब 12 अगस्त को शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह आनजा जिले के चागलगम के पास स्थित इलाके में गया था और उन्होंने इस सूचना के सत्यता की पुष्टि की थी।

गावो के मुताबिक पीएलए के करीब 200 जवानों ने छह बिना सैनिकों वाले चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया जो इस इलाके में गश्त के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा बनाए गए अस्थायी शिविर थे। छागलगम वह अंतिम प्रशासनिक बिंदु है जो मैकमोहन रेखा से करीब 108 किलोमीटर दक्षिण में है। उन्होंने व्याख्यायित किया कि जबसे अतिक्रमण हुआ है, करीब 1,500 सा 1,600 लोग लगातार आतंक में जी रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने साफतौर से इसकी सूचना राजधानी ईटानगर तक पहुंचा दी है।

जैसा कि लद्दाख में देखा गया है, एक समस्या यह है कि इस इलाके में सेना की तैनाती नहीं है। भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के करीब 70 से 80 जवान ही चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए बचे हैं।

एक और स्थानीय स्रोत का कहना है: "हमारे तरफ से चीनी सैनिकों द्वारा कब्जाए गए इलाके तक जाने वाली कोई सड़क या नियमित आपूर्ति व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से भारतीय सेना को पैदल ही जाना पड़ता है। स्थिति काफी दयनीय है क्योंकि स्थानीय जनता इस बात से चिंतित है कि चीनी पीएलए के जवान इस कब्जाए गए इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझती?

एक सूत्र ने दि इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और मतभेदों को दूर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सूत्र ने बताया, "चीनी सैनिकों ने कब्जाए गए जगह पर टेंट लगाए थे, लेकिन उसे अगले दिन ही हटा लिया। दोनों पक्षों में

बने गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 9 जम्मू–कश्मीर राइफल्स के जवान छगलागम सेक्टर में चीनी सैनिकों के आमने–सामने हैं।"

विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कहती हैः "केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बने सभी घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी सभी उपाय किए जाएंगे।" गौर करने की बात यह है कि छगलागम में पीएलए का नवीनतम अतिक्रमण चीन के चेंगदू सैन्य क्षेत्र के सैनिकों ने किया है, न कि लाजहू सैन्य क्षेत्र के सैनिकों ने जो कि लद्दाख और मध्य क्षेत्र (बाराहोटी) में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

इससे पता चलता है कि बीजिंग का केंद्रीय सैन्य आयोग भारत को तंग करने के लिए समन्वित तरीके से प्रयास कर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से देखें तो चीन लगातार भारत से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के एक स्थानीय अखबार ने इस बारे में लिखा कि "अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने संसाधनों को उन्नत बनाने में दिल्ली की केंद्र सरकार हिचक रही है।"

अखबार ने लिखाः "एक साफ उदाहरण अजवा जिले में छगलागम चौकी के पास भारत–चीन सीमा के सीमांकन का है। उपयुक्त सीमांक न होने की वजह से चीनी सेना अक्सर ग्लाई ताकरे और हादिरा ताकरे नाम के दो दर्रों से घुसपैठ कर जाती है, जो कि छगलागम में बने आईटीपीबी के अंतिम आधार शिविर से करीब 100 किमी. दूर हैं।

उस समय अंजा जिला परिषद की चेयरपर्सन बी तेगा ने साफ किया कि चीनी अक्सर उस इलाके में अतिक्रमण कर जाते हैं वे "भारतीय क्षेत्र के पत्थरों और पेड़ों पर अज्ञात तरह के चिह्न एवं प्रतीक बनाकर जाते हैं।" तेगा ने कहा कि चीनियों के जाने के बाद भारतीय गश्ती दल तत्काल ही चीनी सेना द्व ारा बनाए गए चिह्न को मिटा सकते हैं। जिला परिषद की नेता ने कहा, "भारत सरकार को सुरक्षा और सीमा पर आसानी से निगरानी के लिए तान्या, पोमपोम और लाईटाकरू इलाके में सैन्य शिविर स्थापित करना चाहिए।"

वर्ष 2012 में छागलागम जिले के अधिकारियों ने स्थानीय प्रेस को बतायाः "छागलगम से ग्लाई ताकरे और हदिर ताकरे तक गाड़ियां चलाने लायक समुचित सड़कों के अभाव में भारतीय गश्ती दल को सीमा तक पहुंचने में 4–5 दिन लग जाते हैं, यह आपातकालीन स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है।" अधिकारियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि छागलगम–हायुलियांग सड़क को सेना के वाहनों और अन्य भारी वाहनों के चलने लायक चौड़ा किया जाए।

बी तेगा ने कहाः "चीन सरकार ने अपने सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए राजमार्ग बनाए हैं। दूसरी तरफ, भारत आज भी अरुणाचल प्रदेश की सभी सीमा चौकियों तक जाने लायक सड़क नहीं बना पाया है।

चीनियों का अतिक्रमण सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 25 जुलाई को उच्च सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पीएलए के करीब 21 जवान उत्तराखंड के बराहोटी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर गए हैं। ऐसा लगता है कि ये चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब एक घंटे रहने के बाद वापस लौट गए। एचटी की खबर में कहा गया हैः "इस महीने 16–17 जुलाई को चुमार में सीधे आमना–सामना होने के अलावा यह चीनी सेना का तीसरा अतिक्रमण है। इसके पहले 12–13 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा में भी अतिक्रमण का मामला सामने आया था।"

खासकर मध्य क्षेत्र की यह घटना भारत और चीन द्वारा मानचित्रों के आदान–प्रदान के बाद हुई है। यह एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां यह आदान–प्रदान हुआ था। इस अतिक्रमण से कुछ ही दिनों पहले संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) गौतम बंबावाला एलएसी पर शांति बनाए रखने की चर्चा करने के लिए एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से मिले थे, जिसका नेतृत्व वहां के महानिदेशक (सीमा मामले) कर रहे थे। यह दो दिवसीय आधिकारिक स्तर की बातचीत वर्ष 2012 के समझौते के तहत हुई जिसमें भारतीय और चीनी पक्ष ने एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए चर्चा की। उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने स्वीकार किया थाः "प्रतिनिधिमंडल ने भारत–चीन सीमावर्ती इलाके में हाल में हुए घटनाक्रम पर चर्चा की है।"

स्वाल यह है कि जब 1993, 1996, 2005 और 2012 के समझौते चीनी आक्रामकता को रोकने में नाकाम रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पांचवें समझौते से ऐसा हो सकेगा? चीन का तर्क यह है कि नए समझौते से शांति इस शर्त पर आ सकती है कि भारत सीमावर्ती इलाके में किसी भी तरह का विकास कार्य रोके।

आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर भी चर्चा की कि, "सीमा पार नदियों के इस्तेमाल के बारे में समझ बढ़ाने की जरूरत है।" इससे यह संकेत मिलता है कि चीनी भारत की इस आशंका को दूर करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था अपनाने को तैयार नहीं हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल की धारा मोड़ी जा रही है।

अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे और भारत की जनता को बताए कि इस पर क्या हो रहा है। नेहरू लगातार श्वेत पत्र जारी किया करते थे (वर्ष 1959 से 1965 के बीच 15 श्वेत पत्र जारी हुए थे)। मौजूदा सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? किसी भी तरह से यह समझदारी भरा कदम होगा, इसके पहले कि कुछ बाबू लोग प्रासंगिक फाइल को गायब कर दें।

(लेखक भारत–चीन रिश्ते के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने 'फेट ऑफ तिब्बत' नामक पुस्तक भी लिखी है)

नई दिल्ली में 9 सितंबर 2013 को पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर इसके कुछ अंश का पाठ करती हुई सेरिंग वांगमो

अ होम इन तिब्बत

तिब्बत से एक रहस्यमय भूमि की तस्वीरें जेहन में उभरती हैं। बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की चोटियां नीले आसमान को बेधती हैं और घास के मैदानों में बहने वाली ठंडी हवाएं हाड़ को कंपा देती हैं। कत्थई लबादे वाले बौद्ध भिक्षु सुदूर मठों में प्रार्थनाएं करते रहते हैं और हत्थे–कत्थे घुड़सवार ऊबड़–खाबड़ जमीन को रौंदते रहते हैं। ऊंचे पठार पर रहने वाले लोग दुष्कर रीति–रिवाजों का पालन करते हैं जैसे फटे–पुराने कपड़ों में लेट–लेट कर सैकड़ों मील की तीर्थ यात्रा करना। भावनाएं, जादू–टोना, भूत–प्रेत तिब्बत का हिस्सा हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि तिब्बत एक विचित्र दुनिया है।

तिब्बत की ऐसी छवि असल में पश्चिमी यात्रियों और अन्वेषकों द्वारा पिछली शताब्दी में लिखी गई पुस्तकों से उभरती है जिससे तिब्बत को रहस्यमय रखने में मदद मिली है। जब कम्युनिस्ट शासकों ने 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा किया और वहां के लोगों पर चीनी भाषा एवं संस्कृति थोपने लगे तो तिब्बत का अपना इतिहास पृष्ठभूमि में जाने लगा। इस प्रकार भारत एवं नेपाल में एक शरणार्थी की तरह पलने–बढ़ने वाली युवा लड़की वांगमो धोम्पा के लिए अंग्रेजी में तिब्बत के बारे में बस वही पुस्तकें उपलब्ध थीं जो कि पश्चिमी नागरिकों ने लिखे थे, इसलिए वह इस देश को एक निषिद्ध क्षेत्र ही समझती थी, एक ऐसी जगह पहाड़ों, काले जादू के नाटकीय पृष्ठभूमि में परिकल्पना और दंतकथाएं हावी हैं और लोग अजीबोगरीब रीति–रिवाजों और दिखावटी चीजें करते हैं।

ऐसी प्रस्तुतियों के बोझ से दबी सेरिंग धोम्पा और पूर्वी तिब्बत के नांगछेन में स्थित अपने एक नोमैडिक मूल गांव के बारे में लिखने की कोशिश करती हैं। वह तिब्बत के बारे में एक ऐसे तरीके से बताने के लिए जूझती हैं, जो "अतीत के प्रभाव या रंगी–पुती मौजूदा धारणाओं के असर से मुक्त हो।" हालांकि अतीत महत्वपूर्ण है खासकर ध ोम्पा के लिए जिनके परिवार के सदस्य सैकड़ों साल तक गांव के मुखिया रहे हैं। सेरिंग उन कुछ तिब्बती लेखिकाओं में से हैं जो ऐसे साहित्य संसार का सृजन करने की कोशिश कर रही हैं जिसमें तिब्बती स्वर हो, पश्चिम के रोमानी पेशकश से अलग। वह मूलतः एक कवियत्री हैं और उनकी कविताएं अमेरिका में प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन भारत में हाल में पेंगुइल द्वारा जारी "अ होम इन तिब्बत" में वह बिना भावुकता के व्यक्तिगत इतिहास और क्षति की ताकतवर कथा को बुनने की कोशिश करती हैं। कभी–कभी अतीत की याद के घुमाव के साथ उनके इस गतिशील वर्णन में तिब्बत ही मुख्य चरित्र है, एक ऐसी भूमि और वहां के लोग जो लगातार दमन का शिकार हैं।

अपनी मां से सेरिंग को यह पता चला कि तिब्बत उनका असली घर है, लेकिन यह छवि भी नुकसान और कई असंगत चीजों की थी। तिब्बत उनके लिए एक निषिद्ध क्षेत्र था क्योंकि वह तिब्बती थीं। वह भारत में निर्वासन में पैदा हुई थीं और भारत एवं नेपाल में पली–बढ़ी थीं। उनके जेहन में तिब्बत उनकी मां की कहानियों की वजह से जिंदा रहा है। हाल में नई दिल्ली आई सेरिंग ने कहा था, "यह एक ऐसी भूमि है जिसकी जानकारी काफी हद तक मेरी मां के अतीत मोह से मुझे मिली थी। उनके जीवन के खुशगवार दिन तिब्बत में ही बीते थे। जो तिब्बत के हैं और जो नहीं हैं, यह दोनों के लिए उत्कंथा और जिज्ञासा का विषय हो सकता है। सभी इस मूल बात पर सहमत तो होंगे कि तिब्बत में शांति जैसा कुछ नहीं है।"

निर्वासन में कई साल रहने के बावजूद सेरिंग की मां को लगता था कि एक दिन वह अपने घर वापस जाएंगी। लेकिन इसके पहले कि उनका यह सपना पूरा होता उत्तर भारत में एक हाईवे पर ठंड की कोहरे वाली सुबह हुई एक भीषण कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया। अपने मां की अकेली संतान सेरिंग न केवल मां को खो बैठीं, बल्कि तिब्बत के साथ अपने भावुक संपर्क को भी जिसने धीरे–धीरे उनके दिमाग में बड़ी जगह बना ली थी।

"अ होम इन तिब्बत" एक मां और मातृभूमि को दिया गया सम्मान है, लेकिन एक ऐसा प्रयास भी जिससे निर्वासन के जीवन और देश एवं राष्ट्रीयता से जुड़े रिश्ते को समझने की कोशिश की गई है। तिब्बत के भविष्य के बारे में कोई रास्ता बताने के बारे में सेरिंग अपनी अनिश्चितता का खुलासा करती हैं। वह बताती हैं कि एक ही साथ एक दूर स्थित देश की सुखद कल्पना और एक कब्जे वाले तिब्बत की सच्चाई के साथ रहने में कितनी मुश्किल आती है।

अपनी मां की मौत के बाद सेरिंग पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं, लेकिन तिब्बत उनके दिल के और करीब आता गया। आखिरकार जब उन्होंने पहली बार अपनी मां के अंतिम अवशेषों के साथ धोम्पा का पहला दौरा किया तो वह भूमि और वहां के लोग उन्हें इतने परिचित लगे जिसने उन्हें सैनफ्रांसिस्को के अपनी मौजूदा दुनिया से दूर कर दिया।

सेरिंग लिखती हैं, "हम आकांक्षाओं पर जिंदा हैं, हमारी उम्मीदें काफी हद तक हमारी नहीं हैं, हमारी ताकत हमारी नहीं है। लेकिन हम सपने आसानी से देख सकते हैं। हम एक ऐसे देश लौटने का सपना देख रहे हैं जिसे हमारे युवा साथियों ने कभी नहीं देखा है।"

"अ होम इन तिब्बत" अब कम से कम तिब्बत की ऐसी छवि तो पेश कर रही है जो एक दुःखी तिब्बती हृदय ने देखा है।

लेखिकाः सेरिंग वांगमो धोमपा
प्रकाशकः पेंगुइन बुक्स इन इंडिया
पेज 320 कीमतः 499 रुपए